प्रतिदिन

कश्मीर में बदलाव

जम्मू-कश्मीर के शासन-प्रशासन में सुधार का क्रम जारी है और इसी कड़ी में लोकसभा में दो संशोधन विधेयकों का पारित होना सुखद व स्वागतयोग्य है. देश के अनुरूप इस केंद्रशासित प्रदेश को मुख्यधारा में लाने के तमाम प्रयास जरूरी हैं. जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक के पारित होने से इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व में विस्तार होगा. कश्मीरी प्रवासी समुदाय के दो प्रतिनिधि और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से विस्थापित लोगों का भी एक प्रतिनिधि केंद्रशासित प्रदेश की विधानसभा में नामित किया जाएगा. यह बात छिपी नहीं है कि विगत वर्षों में बड़ी संख्या में लोग जम्मू-कश्मीर से पलायन करने को मजबूर हुए हैं. यह संख्या एक से तीन लाख तक बताई जाती है. पलायन करने वालों में पंडितों की संख्या सबसे ज्यादा है. जो एक बार घाटी से निकले, तो फिर लौट न पाए. बड़ी संख्या में ऐसे कश्मीरी पंडित हैं, जो कभी कश्मीर जाने की हिम्मत नहीं कर सके. ऐसे लोगों के बीच से जब प्रतिनिधि विधानसभा के लिए नामित होंगे, तो जाहिर है, वंचितों-शोषितों को एक आधिकारिक आवाज मिलेगी, अपनी विधानसभा में उनका दर्द भी दर्ज होगा. अत यह एक बड़ी जरूरी राजनीतिक-सामाजिक पहल है, इससे अलगाववादियों को भी मुंहतोड़ जवाब मिल सकेगा.

इसके अलावा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का भी एक प्रतिनिधि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नामित होगा. जाहिर है, इसमें ऐसे कश्मीरी नेताओं को आवाज मिलेगी, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हैं और कहीं बाहर रहने को मजबूर हैं. पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने के संकल्प के मद्देनजर यह पहल महत्वपूर्ण है. वास्तव में, विधानसभा में कश्मीरी पंडितों और पाक अधिकृत क्षेत्र के कश्मीरियों की आवाज के बिना जम्मू-कश्मीर की बात पूरी नहीं होती थी. देखने में ये कदम छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव विशेष रूप से घाटी की राजनीति पर पड़ना तय है. अब यह सरकारों पर निर्भर करेगा कि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में योग्यतम प्रतिनिधित्व पहुंचे और शांति-समाधान की दिशा में काम करे. कोरी राजनीति से अलग कश्मीर के व्यापक हित के बारे में सोचने का समय है. वहां धीरे-धीरे सामान्य हो रही स्थितियों को हर प्रकार से सकारात्मक बल देना होगा. आंकड़े गवाह हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे तथ्यों के साथ लोकसभा में बताया है कि पहले और आज के कश्मीर की जमीनी हकीकत में बहुत बदलाव आया है. कश्मीर में जनजीवन जैसे-जैसे सामान्य हो रहा है, उससे सरकार की भी उम्मीदें बढ़ रही हैं.

साथ ही, जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक के जरिये कश्मीर में आरक्षण का वही स्वरूप हो जाएगा, जो बाकी देश में है. देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के अनुरूप ही आरक्षण में एकरूपता जरूरी है. पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ देना जरूरी है, ताकि चंद लोगों का परंपरागत वर्चस्व टूट जाए. कश्मीर में ही बड़ी संख्या में ऐसी जातियां रही हैं, जो आरक्षण या किसी भी प्रकार की विशेष सहूलियतों से वंचित हैं, ऐसी तमाम जातियों को विधिवत आरक्षण देकर आगे बढ़ाना कश्मीर के लिए लाभप्रद है. अब पिछड़े गांवों में रहने वाले सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित लोगों व नियंत्रण रेखा के करीब रहने वालों को भी आरक्षण मिल सकेगा. जाहिर है, हम नए विकासशील कश्मीर की ओर बढ़ रहे हैं.

'इंडिया' की अंदरूनी चुनौतियां

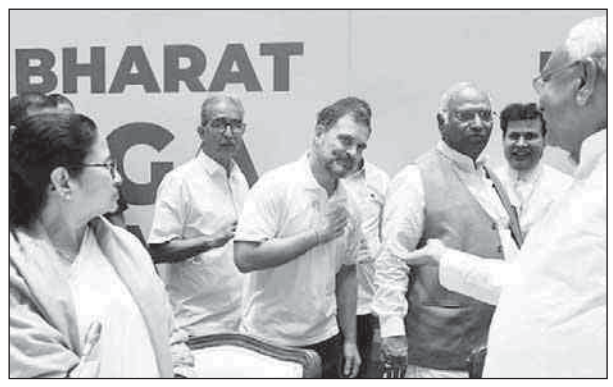

तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों में अप्रत्याशित हार के बाद उपज रही निराशा से 'इंडिया' गठबंधन पर टूट का खतरा मंडरा रहा है. उसे अपनी गतिविधियों के व्यापक प्रबंधन के लिए एक पूर्णकालिक संचालक की दरकार है, पर दिक्कत यह है कि कांग्रेस की योजना में संयोजक का पद 'अनावश्यक' माना जा रहा है.

राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीन हिंदी भाषी राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली अप्रत्याशित और अपमानजनक पराजय के बाद कांग्रेस को 'इंडिया' गठबंधन के भीतर से भी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बमुश्किल 48 घंटों के बाद ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख कमलनाथ ने ईवीएम मशीनों के खिलाफ एक सामूहिक मुहिम के लिए जरूरी समर्थन जुटाने हेतु ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार तक पहुंचने की कोशिश की.

दरअसल, कमलनाथ चाहते हैं कि 'इंडिया' गठबंधन चुनावों पर न्यायमूर्ति मदन लोकुर की अध्यक्षता वाले सिटिजन कमीशन की सिफारिशों को जोर-शोर से उठाए, जिनके अनुसार ईवीएम मशीनें सत्यापन योग्य नहीं हैं. सिटीजन पैनल के एक सदस्य सुभाशीष बनर्जी का तर्क है कि ईवीएम मशीन के स्रोत कोड को सार्वजनिक होना चाहिए या ईवीएम में केवल एक बार प्रोग्राम करने वाली चिप का ही इस्तेमाल होना चाहिए इत्यादि बातें केवल मुख्य मुद्दे से भटकाने का काम करती हैं.

अगर ये सभी मांगें मान भी ली जाएं (माना भी जाना चाहिए), तब भी ईवीएम सत्यापन योग्य नहीं होंगी. लेकिन ईवीएम के कथित दुरुपयोग के लिए 'इंडिया' गठबंधन का समर्थन पाने की कमलनाथ की इस कोशिश में एक बड़ा दोष है. पहला, यह पराजित पक्ष का तर्क है, और, दूसरा, ईवीएम से छेड़छाड़ का यह तर्क तेलंगाना में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के संदर्भ में अपना अर्थ खोता दिखता है, जहां उसने बीआरएस और भाजपा, दोनों को प्रभावशाली अंतर से हराया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान 'अखिलेश वखिलेश' कहते हुए 'इंडिया' गठबंधन के सहयोगियों को प्रदेश से बाहर रखने के बाद कमलनाथ जिस दुस्साहस के साथ सहयोगियों से समर्थन मांग रहे हैं, उससे अखिलेश, ममता और नीतीश चकित हैं.

यह भी याद किया जा सकता है कि तीन महीने पहले सितंबर में दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर विपक्ष के 13 सदस्यीय पैनल की एक बैठक हुई थी, जिसमें 'इंडिया' गठबंधन ने अक्तूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में महागठबंधन की पहली बैठक के लिए सहमति जताई गई थी. लेकिन कमलनाथ ने ऐसी किसी सार्वजनिक बैठक की मेजबानी से इन्कार कर दिया था, जो भाजपा सरकार में बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर केंद्रित होगी. भोपाल में 'इंडिया' गठबंधन की बैठक को लेकर कमलनाथ के विरोध को कई तरह से देखा जा सकता है. उनका तर्क था कि प्रस्तावित गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, जो राज्य विधानसभा चुनाव में उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था, जो उन्हें लगा कि वह आसानी से जीत रहे हैं. उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयगिरि द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी से उपजे विवाद की भी जानकारी थी. वह समाजवादी पार्टी, जदयू और वामपंथियों के साथ कुछ ही सीटों को लेकर किसी भी तरह के समझौते के पक्ष में नहीं थे. सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव ने इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाया, जिसे नीतीश कुमार और ममता बनर्जी का समर्थन भी मिला. दरअसल, मध्य प्रदेश में इस 'अन्य' वर्ग के वोट भाजपा के खाते में पड़े, जिसने भाजपा के वोट प्रतिशत को 46 फीसदी तक पहुंचा दिया, जबकि कांग्रेस 40 फीसदी पर ही ठहर गई.

सवाल यह है कि क्या कमलनाथ इस झड़प को टाल सकते थे? व्यापक तौर पर देखें, तो 'इंडिया' गठबंधन के कुछ सहयोगी अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. सीटों के बंटवारे के प्रस्तावित फॉर्मूले को अब टीएमसी, समाजवादी पार्टी, जदयू और आप की तरफ से ज्यादा विरोध का सामना कर पड़ सकता है. निराशा या अवसरवादिता के चलते 'इंडिया' गठबंधन के टूटने का भी खतरा है, क्योंकि, विपक्ष को डर सताने लगा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे लगभग तय ही हैं.

दरअसल, 'इंडिया' गठबंधन की सभी वार्ताओं में गांधी परिवार एक कमजोर कड़ी बना हुआ है. कांग्रेस में राहुल और प्रियंका गांधी की कोई भूमिका तय नहीं है. मल्लिकार्जुन खरगे को अखिल भारतीय कांग्रेस के 88वें अध्यक्ष बने बेशक एक साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन यह बात फैली हुई है कि किसी भी राजनीतिक फैसले या मंजूरी के लिए वह राहुल गांधी के पास जाते हैं. तो, आखिर कांग्रेस के लिए आगे की राह क्या बचती है? विपक्ष या 'इंडिया' गठबंधन को यथाशीघ्र चुनाव- प्रबंधन के तंत्र, वार्ता के बिंदु और सोशल मीडिया नीति को दुरुस्त कर लेना चाहिए.

गठबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल नरेंद्र मोदी का है. क्या मतदाताओं की नजर में संभावित विकल्प बने बगैर मौजूदा प्रधानमंत्री से सवाल करना या उनकी आलोचना करना उचित है? 'इंडिया' गठबंधन के लिए कैच-22 (विरोधाभाषी स्थितियों में फंसना) जैसी स्थिति हो गई है. उन्हें मोदी को कठघरे में भी खड़ा करना है, और अपने बीच से किसी को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर न दिखाने को लेकर उनमें तकरीबन सहमति भी है. इसी तरह जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दों पर राहुल गांधी का खास जोर और धार्मिक कार्यक्रमों में बदलाव लाने के कांग्रेस के प्रयास कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं.

कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन में कई लोग ऐसे हैं, जो जाति जनगणना के मुद्दे पर ज्यादा विचार-विमर्श की जरूरत को मानते हैं. इसी तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ द्वारा शुरू किए गए हिंदुत्व समर्थक कार्यक्रमों पर भी बात होने की पूरी उम्मीद है. 'इंडिया' गठबंधन को अपनी गतिविधियों के व्यापक प्रबंधन के लिए एक पूर्णकालिक संयोजक की भी जरूरत है, जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है. किसी से छिपा नहीं है कि इसके लिए ममता बनर्जी, शरद पवार और नीतीश कुमार इसके कुछ दावेदार हैं, बशर्ते कांग्रेस नेतृत्व (गांधी परिवार और खरगे), उनसे औपचारिक अनुरोध करें.

दिक्कत यह है कि कांग्रेस की योजना में संयोजक का पद कुछ अस्पष्ट वजहों से 'अनावश्यक' माना जा रहा है. इन चुनौतियों को देखते हुए ममता, नीतीश और अखिलेश जैसे 'इंडिया' गठबंधन के नेता चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी तरफ से सुलह के कुछ संकेत दे और अनौपचारिक तौर पर गठबंधन का नेतृत्व क्षेत्रीय दलों को सौंपे. यह कड़वी दवा ही कांग्रेस के लिए एकमात्र उपचार है, जिसके लिए वक्त तेजी से खत्म होता जा रहा है.

- रशीद किदवई

शादी के सीजन में चमकता सोना, पर खदानों में घट रही है 'दमक'

त्योहारों और शादियों के समय सोना महंगा हो जाता है. पर खदानों में सोने का रिजर्व घटते जाने से इसके दाम अकल्पनीय ऊंचाई पर जा सकते हैं.

दुर्लभ पीली धातु इस समय सारी दुनिया को चकाचौंध कर रही है. दुनिया भर के कमॉडिटी मार्केट में इसकी चमक है और न्यूयॉर्क कमॉडिटी एक्सचेंज में तो यह 2,000 डॉलर प्रति औंस की सीमा को तोड़ता हुआ 2,028 डॉलर प्रति औंस पर जा पहुंचा. ऐसे में, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही हालात रहे, तो अगले साल के अंत तक सोना 2,200 डॉलर प्रति औंस पर जा पहुंचेगा.

भारत में इस समय शादियों का सीजन चल रहा है और सोना 62,287 रुपये प्रति 10 ग्राम है. देश में सोना घरेलू कारणों की तुलना में अंतरराष्ट्रीय कारणों से प्रभावित होता है, क्योंकि अपने यहां सोने का उत्पादन नगण्य है, जबकि किसी जमाने में यहां सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा था. कोलार की खानें कभी सोना उगलती थीं. अंग्रेजों ने 121 सालों तक यहीं से सोना लूटा और बेहद कठिन परिस्थितियों में मामूली मजदूरी पर लोगों से काम करवाया. आजादी के बाद सोने का उत्पादन कम हो गया, लेकिन 2001 में यहां सोने का उत्पादन बंद ही हो गया. उसके बाद से भारत पूरी तरह से सोने के आयात पर निर्भर हो गया.सोने के प्रति भारतीयों के मोह ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश बना दिया. आज देश सालाना औसतन 700 टन सोने का आयात करता है और इसकी वजह से भारत का व्यापार संतुलन गड़बड़ा गया है. कच्चे तेल के बाद हम सोने का ही सबसे ज्यादा आयात करते हैं, जिसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है, जबकि चांदी का औद्योगिक उपयोग है. इस साल सोने का आयात घटकर 650 टन होगा, क्योंकि विश्व बाजार में सोना महंगा हो गया है.अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने के मूल्य अमेरिका की आर्थिक नीतियों तथा डॉलर के उतार-चढ़ाव पर कमोबेश निर्भर करते हैं. उत्पादन घटने से तो सोना महंगा हो ही रहा है, जब दुनिया में प्राकृतिक या मानवीय विपदा आती है, तब भी सोने की कीमत बढ़ जाती है. सोना मुसीबत का सच्चा साथी है. इसलिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने पास सोना जमा रखते हैं और जरूरत के हिसाब से बेचते-खरीदते भी हैं.कोविड महामारी के समय भी सोने की कीमतें चढ़ गई थीं और जब ईरान-अमेरिका युद्ध के कगार पर जा पहुंचे थे, तो भी ऐसा ही हुआ. अभी रूस-यूक्रेन युद्ध और इस्त्राइल-हमास संघर्ष में भी ऐसा ही हुआ. इसकी कीमतें इन कारणों से बढ़ी हैं. लेकिन एक बड़ा कारण यह है कि अमेरिका में इस समय सरकारी बांडों का मूल्य तेजी से गिर रहा है तो दूसरी ओर डॉलर भी महत्वपूर्ण मुद्राओं के मुकाबले नीचे जा रहा है. डॉलर के गिरने का मतलब यह है कि अन्य महत्वपूर्ण मुद्राएं ऊपर जा रही हैं जिससे उन देशों के निवेशक सोना खरीदते हैं. डॉलर और सोने की कीमतों में सीधा संबंध है और इस समय जैसे-जैसे डॉलर गिर रहा है, सोने के दाम बढ़ रहे हैं.

सोने में बड़े पैमाने पर सट्टा लगता है और अमेरिका की कुछ कंपनियां तो अरबों डॉलर का सट्टा सोने पर लगाती हैं, जिससे इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव आता रहता है. सोने की खदानों में अब रिजर्व भी घटता जा रहा है. आने वाले समय में अगर नए रिजर्व नहीं मिले, तो सोना अकल्पनीय ऊंचाई पर जा सकता है. इसके अलावा अमेरिकी फेडरल बैंक को यह बात समझ में आ गई है कि महंगाई रोकने के लिए मौद्रिक नीति के इस्तेमाल की अपनी सीमाएं हैं. यानी ब्याज बढ़ाकर महंगाई घटाने का तरीका घिस-पिट गया है, क्योंकि अब मुद्रास्फीति के लक्षण भी बदल गए हैं. अमेरिका में मुद्रास्फीति अब भी ज्यादा है और इस कारण सोने के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि बड़े निवेशक इसमें निवेश कर रहे हैं. पर भविष्य में जब मुद्रास्फीति कम होगी, तो सोने की कीमत भी गिर जाएगी. फिर रूस-यूक्रेन तथा इस्त्राइल-हमास के बीच चल रहे युद्ध रुकने की संभावना को देखते हुए भी सोने के दाम घटने की उम्मीद है.

अपने यहां पर्व-त्योहारों- जैसे अक्षय तृतीया और दिवाली में सोने की खरीद में तेजी आने से भी उसकी कीमत बढ़ जाती है. फिर चूंकि यहां सोने पर लगभग 17 फीसदी टैक्स है, इस वजह से यह हर देश से महंगा है. महंगा होने के कारण बाजारों में हल्के गहनों की बिक्री ज्यादा है.

- मधुरेंद्र सिन्हा

दक्षिण के किसानों को भी पहुंचा भारी नुकसान

फिर रुला गया एक चक्रवाती तूफान

इस तूफान ने मछुआरों के अलावा दक्षिण के किसानों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है. यह खरीफ की कटाई का मौसम है. खेतों में धान की फसल अंत में हफ्ते-डेढ़ हफ्ते सूखने के लिए छोड़ दी जाती है. मगर इस तूफान ने धान की बालियों को जमीन पर गिरा दिया है

मिचौंग चक्रवात जब तमिलनाडु के तट से 80-100 किलोमीटर दूर केंद्रित था और व्यापक असर डाल रहा था, तभी करीब 400 किलोमीटर दूर मेरे शहर बेंगलुरु में भी ठंडी-ठंडी हवा चलने लगी थी. 3 दिसंबर को चेन्नई में सबसे ज्यादा बारिश हुई, तो 3 और 4 दिसंबर को यहां भी रुक-रुककर बारिश होती रही, जबकि बेंगलुरु कर्नाटक का हिस्सा है. फिर जैसे-जैसे तूफान उत्तर की ओर बढ़ा, चित्तूर, कडपा, अन्नतपुरामु, अमरावती, नेल्लोर, रायलसीमा जैसे तमाम इलाकों में बारिश होने लगी. जिस तरह शुरूआत में तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, पुडुचेरी जैसे तटीय इलाकों में मिचौंग का असर रहा, और बाद में यह सुदूर इलाकों में पहुंचा, वैसे ही अब कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के सुदूर इलाकों में बारिश हो रही है.वास्तव में, मानसून के बाद के मौसम, यानी 'पोस्ट-मानसून' में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते रहे हैं. हालांकि, यह अक्तूबर व नवंबर महीने में ज्यादा दिखता था, जबकि दिसंबर में काफी कम. मगर अब दिसंबर में भी इनकी निरंतरता बढ़ सकती है, जिसकी एक बड़ी वजह है, सागर का गरम होना. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्रों में गरमी अवशोषित करने की क्षमता बढ़ गई है, ठीक हमारी आबोहवा की तरह, जो अब ज्यादा गरमी अवशोषित करने लगी है. इस कारण जब कभी चक्रवात या दबाव का क्षेत्र बनता है, तो समुद्री ऊर्जा उसे ज्यादा मारक बना देती है. इस बार पिछले एक महीने से बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र लगातार बन रहा था. अल-नीनो वर्ष में उत्तर-पूर्व मानसून के असामान्य होने की बात भी कही जा रही थी. इन सबका ही एक नतीजा मिचौंग चक्रवात है. तमिलनाडु में सिर्फ चेन्नई के इलाकों में 1 से 4 दिसंबर के बीच कई जगहों पर 50 से 60 सेंटीमीटर तक बारिश हुई, जो काफी ज्यादा है.इस तूफान ने मछुआरों के अलावा दक्षिण के किसानों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है. यह खरीफ की कटाई का मौसम है. खेतों में धान की फसल अंत में हफ्ते-डेढ़ हफ्ते सूखने के लिए छोड़ दी जाती है. मगर इस तूफान ने धान की बालियों को जमीन पर गिरा दिया है. गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नेल्लोर जैसे आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों के डेल्टा क्षेत्र धान के लिए प्रसिद्ध रहे हैं. मगा यहां के किसानों के हाथ सिवाय मायूसी के कुछ भी नहीं है. इसी तरह, यहां नारियल, पपीता, केले, सब्जी और फूलों की भी काफी खेती होती है. विशेषकर कृष्णा, गोदावरी जिलों में इन फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है. अब तो तेलंगाना में भी किसानों को चक्रवाती बारिश चोट पहुंचा रही है.क्या ऐसे तूफानों से बचा जा सकता है? जाहिर है, सबसे पहले हमें जलवायु परिवर्तन से निपटना होगा और ऐसे उपाय करने होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग कम से कम असरंदाज हो सके. कार्बन-उत्सर्जन का हरसंभव प्रबंधन करना होगा. मगर कुछ प्रयास तत्काल किए जा सकते हैं. मिसाल के तौर पर, चक्रवात के बनने का पूर्वानुमान, यानी साइक्लोजेनेसिस न सिर्फ समय पर प्रसारित हो, बल्कि निचले स्तर तक यह सूचना जाए. अभी आमतौर पर हफ्ते में एक बार यह सूचना जारी की जाती है, पर यदि अक्तूबर से दिसंबर तक के महीने में करीब दस दिन पहले यह सूचना आ जाए, तो किसानों को अपनी खड़ी फसल को काटने या उसके प्रबंधन का कुछ वक्त मिल जाएगा. इसके लिए, कृषि विभाग और मौसम विभाग के समन्वय से एक तंत्र बनाना चाहिए, जो ठीक उसी तरह का तंत्र हो सकता है, जैसे अभी आपदा प्रबंधन का है. आपदा प्रबंधन के तहत जैसे ही किसी आपदा की सूचना आती है, तो जिन-जिन इलाकों में जान-माल के प्रभावित होने की आशंका होती है, वहां के लोगों व मवेशियों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है.प्रभावित इलाकों में आश्रय गृह भी बनाए जाने चाहिए. दरअसल, तटवर्ती इलाकों में मछुआरों का रहना मजबूरी भी है, इसलिए गांव में पक्का मकान होने के बावजूद यहां वे कच्चे मकानों में रहते हैं. अगर चक्रवात की सूचना मिलते ही उनको 'शेल्टर हाउस' भेज दिया जाए, जो विशेष तौर पर चक्रवात के खिलाफ बनाए गए हों, तो इंसानी जान का नुकसान हम काफी कम कर सकते हैं. इसके लिए भी समग्र प्रयास की दरकार होगी.

पीयूष पंकज.

मनसा वाचा कर्मणा

जीवन के निहितार्थ समझिए

जीवन के बारे में यंत्रवादी मत यह है कि मनुष्य चूंकि अपने वातावरण तथा विविध प्रतिक्रियाओं का परिणाम मात्र है, जो केवल इंद्रियों द्वारा ही प्रत्यक्ष हो सकता है, इसलिए वातावरण और प्रतिक्रियाएं एक ऐसी बुद्धिसंगत प्रणाली से नियंत्रित होनी चाहिए, जिसमें व्यक्ति को केवल बने-बनाए ढांचे के भीतर ही कार्य करने की अनुमति हो. जीवन के प्रति इस यंत्रवादी दृष्टि के पूरे निहितार्थ को समझ लीजिए.

यह मत किसी परम, लोकोत्तर सत्ता की कल्पना नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है, जो निरंतर बना रहे; यह मृत्यु के बाद किसी प्रकार के जीवन को स्वीकार नहीं करता है; इसके अनुसार जीवन और कुछ नहीं, बस एक अल्प-अवधि है, जो पूरी तरह मिट जाने की ओर अग्रसर है. चूंकि मनुष्य पर्यावरणीय प्रतिक्रियाओं के परिणाम के अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसका संबंध बस अपनी स्वार्थपूर्ण सुरक्षा से है, इसलिए शोषण, क्रूरता तथा युद्ध के तंत्र की निर्मिति में उसका योगदान रहा है. इसलिए उसके क्रिया-कलापों को परिवेश के परिवर्तन व नियंत्रण से ही संचालित करना पडेगा.

फिर वे लोग हैं, जो इस मत को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य सारभूत रूप से दिव्य है. उसकी नियति किसी परम प्रज्ञा द्वारा नियंत्रित व निर्देशित है. ऐसे लोग दावा करते हैं कि वे ईश्वर, पूर्णता, स्वतंत्रता, आनंद, अस्तित्व की एक ऐसी अवस्था की खोज कर रहे हैं, जिसमें सभी व्यक्तिपरक अंतर्द्वंद्व मिट जाते हैं. मनुष्य के भाग्य को निर्देशित करने वाली सर्वोच्च सत्ता में उनका विश्वास आस्था पर आधारित है. वे कहेंगे कि इस लोकोत्तर सत्ता या उच्चतम प्रज्ञा ने ही संसार का निर्माण किया है. व्यक्ति अपने आपमें शाश्वत है व उसमें नित्यता का गुण है.

कभी आप सोचते हैं कि जीवन यांत्रिक है तथा कई अवसरों पर, जब दुख और असमंजस घेर लेते हैं, तब आप आस्था की ओर लौट आते हैं, मार्गदर्शन और सहायता के लिए किसी परम सत्ता की ओर ताकने लगते हैं. आप इन दो विपरीत ध्रुवों के बीच डोलते रहते हैं, जबकि इन विपरीत ध्रुवों के भ्रम को समझकर ही आप स्वयं को सीमाओं तथा रुकावटों से मुक्त कर सकते हैं. आप प्राय कल्पना कर लेते हैं कि आप इनसे मुक्त हैं, किंतु आप उनसे मूलभूत रूप से मुक्त ही तभी हो पाते हैं, जब आप इन सीमाओं के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं और इनका अंत कर देते हैं. आप यथार्थ को, 'जो है' उसे तब तक उसकी व्यापकता में नहीं समझ सकते, जब तक अज्ञान की अनादि प्रक्रिया जारी है. जब यह प्रक्रिया थम जाती है, जिसने अपनी लालसा की ऐच्छिक गतिविधियों से स्वयं को बनाए रखा था, तब वह विद्यमान होता है, जिसे कोई चाहे तो यथार्थ कहे, सत्य कहे या फिर परमानंद!

- जे कृष्णमूर्ति

शादी में फिजूलखर्ची रोकें

शादियों का सीजन शुरू हो गया है. देश के विभिन्न शहरों से मिले आंकड़ों के मुताबिक, अगले कुछ दिनों के दौरान कम से कम 38 लाख शादियां होंगी और इन पर कम से कम 4.74 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे. यह सही है कि सांस्कृतिक समृद्धि और पारंपरिक अनुष्ठानों का जश्न मनाया जाना चाहिए, लेकिन भौतिक भव्यता पर अत्यधिक जोर वैवाहिक बंधन की पवित्रता को कमजोर कर सकता है, क्योंकि शादियों में अनावश्यक खर्च से पड़ने वाले आर्थिक दबाव के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं. लिहाजा शादियों में अनावश्यक खर्च की बढ़ती संस्कृति के बारे में चिंतन जरूरी है. ये उत्सव खर्च के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ अपनी परंपरा पर कायम रहते हुए भी मनाए जा सकते हैं, जो न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी जिम्मेदार हैं. अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करके और सादगी की सुंदरता को अपनाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि शादियां वित्तीय तनाव के अनावश्यक भार के बिना प्रेम, एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का सच्चा उत्सव बनी रहें.

- देवेन्द्रराज

विपक्षी गठबंधन में दिखने लगी दरारें

हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जिस औंधे मुंह गिरी है, उसका नुकसान सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, बल्कि पूरे विपक्षी महागठबंधन को होना तय है. अब अन्य दलों के नेताओं को कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका मिलेगा, जिससे इनके बीच की दरारें और स्पष्ट हो जाएंगी. ऐसा शुरू भी हो गया है, क्योंकि इन नतीजों को कोई 'कांग्रेस की हार' बता रहा है, तो कोई 'नेहरू-गांधी परिवार के अहंकार' का नतीजा. स्थिति यह हो गई है कि महागठबंधन की प्रस्तावित बैठक भी आनन-फानन में रद्द करनी पड़ी, क्योंकि विपक्ष के कई नेताओं ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था. ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें ऐसी किसी बैठक का न्योता नहीं मिला है. यह संकेत है कि महागठबंधन में अंदर ही अंदर खींचतान चल रही है, जिसे हालिया विधानसभा चुनावों के नतीजों ने और उजागर कर दिया है. अब मतदाता भी यह समझने लगे हैं कि इन राजनीतिक दलों के नेताओं में एकराय नहीं है और ये सभी अपनी ढपली अपना राग बजाते रहेंगे. ऐसे में, ये भला कैसे अच्छी सरकार का भरोसा मतदाताओं को दे सकेंगे?

कई विपक्षी दलों की यह शिकायत थी कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद राहुल गांधी का रवैया बदल गया है. यहां तक कि 'भारत जोड़ो यात्रा' के बाद से उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर खड़ा किया जाने लगा था. कांग्रेस का यह अति-उत्साह महागठबंधन पर भारी पड़ा. इसी अति-आत्मविश्वास के कारण उसने मध्य प्रदेश में सपा, आप जैसे दलों के साथ कोई समझौता नहीं किया, जिसके बाद अब इन दलों ने खुलकर कांग्रेस को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है. अरविंद केजरीवाल तो कहने भी लगे हैं कि आम आदमी पार्टी ही अब उत्तर भारत में मुख्य विपक्षी दल है, क्योंकि उसके पास दो विधानसभाओं में बहुमत है. इस सबने न सिर्फ कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है, बल्कि 'इंडिया' ब्लॉक की राह में कांटे भी बो दिए हैं. अब साफ-साफ दिख रहा है कि ये नेता भाजपा से नहीं, अपने में ही उलझ रहे हैं और एक-दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे. इससे भाजपा और विशेषकर पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के लिए राहें आसान हो जाती हैं. अब तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्विवाद रूप से तीसरी बार भी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे. विपक्षी नेताओं का वैचारिक द्वंद्व और उनका गिरता मनोबल 'इंडिया' ब्लॉक के लिए चुनावी हार की पटकथा लिख रहे हैं.

- विमल कुमार

प्रतिदिन अखबार

यह पत्र मालिक, प्रकाशक, सम्पादक नानक आहूजा द्वारा देविका वेब प्रिंटर्स, राजापेठ, अमरावती से मुद्रित कर प्रतिदिन अखबार कार्यालय, देविका परिसर, ब्राम्हण सभा के पीछे, दरोगा प्लॉट, राजापेठ, अमरावती 444606 से प्रकाशित किया है. फोन - 0721-2660155/56/57/58 फैक्स - 0721-2677708 E-mail:-pratidinnews@gmail,com प्रतिदिन अखबार में प्रकाशित होनेवाले विभिन्न लेख, पत्र,साहित्य, लेखकों, कवियों आदि के विचारों या तथ्यों पर आधारित होते हैं. इन लेखकों के विचारों अथवा तथ्यों से संपादक की सहमति नहीं है. संपादक पर मात्र सम्पादकीय लेखों का हो दायित्व है. संपादक - नानक आहूजा, समाचार संपादक - प्रवीण आहूजा.